respect of some units have been received. The matter is being processed for further necessary action.

Difference in Foreign investment policies

6437. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have different policies for foreign investments made in India prior to 1989 and those made after 1990;

(b) whether it is a fact that policies are more favourable to foreign investment made after 1990;

(c) if so, the reasons for this discrimination;

(d) the steps proposed to be taken to reduce such discrimination; and

(e) whether there is any move to have an equitable foreign investment policy without regard to the year of investment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c): Government Foreign Investment Policy is governed by the Statement on Industrial Policy laid on the Table of the House on 24th July, 1991.

Under the policy, automatic approvals are being given by the RBI for foreign equity investment upto 51% in higher priority industries listed in Annex, III to the Statement. Other foreign investment proposals, outside the parameters for automatic clearance, are also considered and cleared on merits by the Government. Approvals for the foreign investment, in respect of specified consumer industries are also subject to the condition that remittance of dividends at foreign investment shall be balanced through export earnings.

These policy initiatives are aimed at attracting foreign investment and technology collaboration to obtain higher technology, increase exports and to expand the production base.

The present Foreign Investment Policy is not restricted to fresh proposals made after 24th July, 1991, but earlier approval holders or foreign investors can also take advantage of the new policy.

उत्तर प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने हेतु कार्यदल

6438. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में नए उद्योगों की स्थापना या उनके विकास के लिए किसी कार्य-दल का गठन किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क): 70 वे दशक में की गई कार्यवाही के तहत उत्तर प्रदेश में 41 औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाया गया था।

(ख) और (ग): पिछड़े जिलों में नए उद्योग स्थापित करने अथवा इनका विकास करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किसी कार्य-दल का गठन नहीं किया गया है। इन पहलुओं पर मुख्यतः राज्य सरकारें द्वारा विचार किया जाता है। केन्द्र सरकार परिवहन राज सहायता और करावकाश जैसी क्षेत्र विशेष के लिए विशिष्ट सुविधाएं देकर इन प्रयासों में मदद करती है।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) की सिफारिश पर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को बन्द किया जाना

6439. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उन रूग्ण उपक्रमों को बन्द करना चाहती है जिन्हें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के इस निर्णय से इन उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे;